Export growth declined to (-) 3.28% during Apri-September 1998, following significant deceleration from 21.4% in 1995-96 to 4% in 1996-97 and just 2.6% in 1997-98. As exports constitute 39.7% of total manufacturing output in the country the decline in exports has adversely impacted industrial production.

(c) In order to arrest the slowdown in industrial growth Government have taken various measures during the Budget 1998-99 and thereafter to stimulate and revive industrial growth. The package of measures announced in the Budget inter alia, included.

(i) de-licensing of coal and lignite, and petroleum refining to attract larger inflow of capital (sugar was also subsequenty delicensed).

(ii) increase in limit for aggregate investment by NRIs raised from 5% to 10%.

(iii) rationalisation of tariff structure by introducing 4% special additional duty of customs to remove disadvantages faced by the domestic industry.

(iv) Plan outlay for Energy, Transport and Communications stepped up by 35% to Rs. 61,146 crores in 1998-99 (BE) as against Rs. 45,252 crores in 1997-98 (RE).

(v) Central and State Electricity Regulatory Commissions to be set up to rationalise power tariffs.

(vi) FEMA to be introduced and FERA to be repealed.

(vii) Urban Land Ceiling and Regulation Act (ULCRA) to be repealed, which would lead to a step up in construction activity and demand for materials such as cement, steel etc.

In order to give a further boost to industry Government has announced further measures, which include:

(i) Speciall package announced for revival of growth in exports.

(ii) The Government has recently allowed buy back of shares and inter-corporate loans to boost investment and revive the capital market.

(iii) To give an immediate boost to industrial activity, the busy season credit policy announced by RBI has avoided raising interest rates.

(iv) Counter guarantees given by Government to three major fast track power projects are expected to lead to financial closure and thus create demand for basic and other goods.

(v) Six lane, 7000 km. highways at a cost of Rs. 28,000 crores are to be taken up immediately.

(vi) Government has agreed to permit 40% foreign equity limit in the insurance sector. A Bill to this effect would be introduced in the coming session of the Parliament. The opening up of the insurance sector would provide long term finance for the infrastructure sector.

(vii) Government is conscious of the need for the revival of the industrial sector and has constituted Four Task Forces for Steel, Capital Goods. Commercial Vehicles and Cement to recommend policy interventions to address the problems faced by these sectors. The Task Forces have submitted their recommendations to the Government. The Government has allready notified exemption of seven inputs used in steel manufacturing from the 5% special customs duty. The policy announcements relating to other sectors are expected shortly.

(viii) Government has constituted an Economic Advisory Council to the Prime Minister and the Council on Trade and Industry to the Prime Minister which would discuss policy measures on important economic issues.

It is expected that the slowdown in current years' growth would be arrested and the growth would pick up as a result of the various measures announced.

देश में नमक का उत्पादन

65. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नमक के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा कितने-कितने प्रतिशत है;

(ख) गुजरात और महाराष्ट्र, विशेषकर कच्छ में पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक उद्योग के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन राज्यों में नमक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे है;

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) देश में उत्पादित सामान्य नमक की लगभग 135 लाख टन की औसतन वार्षिक उत्पादन में से महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा निम्न प्रकार से है:-

महाराष्ट्र	2%
गुजरात	72%

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान नमक उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र के नमक उद्योग का निष्पादन निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	जिला	"000" टनों में 1995	नमक उत्पादन 1996	1997
1.	गुजरात	8,824.4	10,403.5	10,096.2
2.	महाराष्ट्र	224.3	245.9	200.6

गुजरात का कच्छ क्षेत्र गुजरात में कुल उत्पादन में 45 लाख टन से अधिक उत्पादन का योगदान करता है। इस क्षेत्र में उत्पादन का जिला-वार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	जिला	"000" टनों में 1995	नमक उत्पादन 1996	1997
1.	कच्छ	2,388.7	2,312.8	2,715.9
2.	सुरेन्द्रनगर	1,822.3	2,155.4	1,505.6
3.	बनासकंठ	313.4	527.3	364.6
जोड़	कच्छ क्षेत्र	4,524.4	4,995.5	4,586.1
जोड़	गुजरात	8,824.4	10,403.5	10,096.2

(ग) नमक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:-

- राज्य सरकारें नमक के विनिर्माण के लिए नये भू-खंडों के आवंटन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर रही है।
- नवीनतम जानकारी से वैज्ञानिक आधारों पर नमक कारखानों की व्यवस्था करने के लिए तकनीकी दिशानिर्देश जारी किये गये है,
- खाद्य, औद्योगिक प्रयोजन और निर्यात के लिए गुणवत्ता वाले नमक की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, राज्यों में नमक परिष्करणशालाओं की अनुमति की जा रही है।
- बाढ़ से प्रभावित होने के उपरान्त नमक कारखानों को अपना उत्पादन पुनः शुरू करने के लिए प्रभावित नमक कारखानों को वित्तीय सहायता के माध्यम से पुनर्वास संबंधी उपायें किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) नमक उपकर आय से अनेक श्रम कल्याण और विकासात्मक कार्यों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इन कार्यों में चिकित्सा सुविधाओं पीने के पानी की सुविधाओं शैक्षणिक सुविधाओं, कार्य स्थलों पर आराम शेडों एवं क्रैचों और श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। विगत तीन वर्षों में श्रम कल्याण और विकासात्मक कार्यों के लिए प्रदत्र सहायता का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	राशि
	(लाख रुपये में)
1995-96	94.4
1996-97	72.7
1997-98	69.0

अनुग्रह सहायता उन नमक विनिर्माताओं को भी दी जाती है जिनके नमक के कारखाने बाढ़, वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई इस प्रकार की सहायता का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	राशि
	(लाख रुपये में)
1995-96	27.0
1996-97	39.9
1997-98	38.0

चालू वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान 3.65 करोड़ रुपये की राशि अनुग्रह सहायता के रूप में उन नमक विनिर्माताओं को प्रदान की गई है। जिनके नमक के कारखाने गुजरात में जून, 1998 में आये चक्रवात से प्रभावित हुए थे।

Restructuring of HMT

66. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Hindustan Machine Tools (HMT) has gone sick;